दैनिक पीपुल्स समाचार, भोपाल

3 JAN 2015

नीति आयोग के गठन का सीएम ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ब्लॉग और ट्विटर पर किए कमेंट्स

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
editor@peoplessamachar.co.in

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत योजना आयोग की जगह प्रधानमंत्री ने स्थापित किए गए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के गठन से भारत के विकास प्रक्रिया में सही अर्थों में संघीय ढांचे की नींव रखी गई है। सीएम ने अपने ब्लॉग और ट्विटर में कहा कि यह आयोग भारत की विकास संबंधी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में काफी मददगार होगा।

मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर तीन बार ट्यूट करते हुए कहा कि एक जनवरी 2015 की नई सुबह भारत ने सहकार और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित विकास के नए युग में आंखें खोली हैं। यह युग प्रवर्तक परिवर्तन भारत योजना आयोग के स्थान पर बनाए गए नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मेटिंग इंडिया के रूप में आया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के चहुंमुखी विकास के लिए जिस योजना आयोग का गठन किया था, वह उस दौर की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में ठीक था। आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकास के नियोजन और योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन में योजना आयोग ने काफी हद तक अच्छा काम किया, लेकिन बीते कुछ दशक में, विशेष कर 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद योजना आयोग के वर्तमान स्वरूप के अस्तित्व की प्रासंगिता लगातार खत्म होती चली गई। लोकतंत्र में विभिन्न प्रदेश में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं। यह बात लगातार महसूस की जा रही थी कि केंद्र में सत्ताधारी दल के राजनीतिक हितों के संवर्धन में आयोग के राज्यों के साथ राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह सहायक होने लगे थे। धनराशि के आवंटन में इसी कारण राज्यों के साथ भेदभाव की बात तीव्रता से महसूस की जा रही थी।

शिवराज ने कहा कि योजना आयोग की कार्यप्रणाली में लोकतांत्रिक भावना का अभाव हो गया था। योजना निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली चर्चा रस्मी हो गई थी। योजनाएं केंद्र से बनाकर राज्यों को भेजी जा रही थीं। इनमें राज्यों की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं का ध्यान नहीं रखा जाता था। इसी कारण योजनाओं का वांछित लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने लगातार यह बात अनेक मंचों से कही कि जिस तरह हर मर्ज की एक दवा नहीं हो सकती, उसी तरह हर राज्य के लिए एक समान योजना नहीं हो सकती।

गांव में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में ग्राम स्तर पर योजनाएं तैयार करने की पहल बहुत महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में उन्होंने यह काम पहले ही कर लिया है। प्रदेश के गांवो के विकास के लिए मास्टर प्लान ग्रामीणों के सुझाव, सहमति और भागीदारी से बनाए गए हैं। इनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह खुशी की बात है कि नया आयोग पूरे देश में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इससे प्रत्येक गांव में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए उनका ज्यादा तेजी से विकास संभव हो सकेगा।